(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली निधियों के अलावा विदेशी ऋणों के जरिए टिहरी परियोजना (4X25 मे.वा.) का क्रियान्वयन किए जाने का प्रस्ताव है । वित्त पोषण संबंधी प्रस्ताव के साथ-साथ हाइड्रो-प्रोजैक्ट इंस्टीट्यूट, मास्को के नेतृत्व में सप्लाईकर्ताओं के कन्सोर्टियम से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ।

राजाध्यक्ष समिति की सिफारिशें

1007. **श्री राम जेठमलानी** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजाध्यक्ष समिति ने सरकार से यह सिफारिश की थी कि देश म विद्युत क्षेत्र का प्लांट लोड फैक्टर कम से कम 58 प्रतिशत होना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि अधिकतर मामलों में विद्युत परियोजनाओं द्वारा प्लांट लोड फैक्टर की राष्ट्रीय औसत दर को कायम नहीं रखा जा रहा है ।

(ग) राज्य बिजली बोर्ड द्वारा संचालित विभिन्न उपक्रमों का प्लांट लोड फैक्टर कितना था ; और

(घ) प्लांट लोड फैक्टर की दर कम होने के क्या कारण हैं ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वी. रंगैया नायडू) : (क) विद्युत सम्बंधी समिति जिसे राजाध्यक्ष समिति के रूप में भी जाना जाता है, द्वारा सिफारिश की गई थी कि प्रणाली के लिए 58% संयंत्र भार गुणक (पी एल एफ) को मार्गदर्शक माना जाना चाहिए परन्तु यह प्रणाली-दर-प्रणाली भिन्न होगा । वर्ष 1992-93 के दौरान 57.1 प्रतिशत औसत अखिल भारतीय पी एल एफ प्राप्त किया गया था ।

(ख) वर्ष 1992-93 के दौरान लगभग 50 प्रतिशत ताप विद्युत केन्द्रों द्वारा 57.1 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से बेहतर पी एल एफ प्राप्त किया गया ।

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों/उपक्रमों का पी एल एफ विवरण (नीचे देखिए) में दिया गया है ।

(घ) ताप विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार गुणक कम होने के मुख्य कारणों में ये शामिल हैं:-कोयले की कम आपूर्ति होना, प्रणाली में मांग कम होने के कारण ताप विद्युत यूनिटों को बन्द किया जाना, निधियों सम्बन्धी समस्यायें होना, नियोजित अनुरक्षण हेतु जबरन बन्द किए गए यूनिटों को पुनः चालू करने में अधिक समय लगना आदि ।

विवरण

वर्ष 1992-93 के दौरान राज्य बिजली बोर्डों/उपक्रमों का पी.एल.एफ. (%) बताने वाला विवरण

राज्य बिजली बोर्ड/ उपक्रम का नाम	1992-93
	पीएलएफ (%)
1	2
दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान	54.0
हरियाणा रा.बि. बोर्ड	49.9
राजस्थान रा. बि. बोर्ड	77.0

1	2
पंजाब रा.बि. बोर्ड	58.3
उत्तर प्रदेश रा.बि. बोर्ड	50.5
गुजरात बिजली बोर्ड	61.6
महाराष्ट्र रा.बि. बोर्ड	59.7
मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	52.5
आंध्र प्रदेश रा.बि. बोर्ड	65.0
तमिलनाडु बिजली बोर्ड	65.2
कर्नाटक बिजली बोर्ड	49.4
बिहार रा.बि. बोर्ड	25.2
उड़ीसा रा.बि. बोर्ड	34.5
प. बंगाल रा.बि. बोर्ड	31.1
प. बंगाल विद्युत विकास निगम	58.1
डी.पी.एल.	28.7
असम रा.बि. बोर्ड	24.3
जोड़ राज्य बिजली बोर्ड	54.1
भारत	57.1

1008. [Transferred to the 5th August, 1993]

Break-down of Power Supply in Trans-Jamuna Area

1009. SHRI GAYA SINGH: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether there is continuous breakdown of power-supply in Laxmi Nagar, Shakarpur area (Trans-Jamuna) Delhi-92, since June 15, 1993;

(b) whether in some cases people have expressed their anger in desperation by demonstration etc.;

(c) is so, the details thereof;

(d) whether DESU authorities are keeping silent and not attending the complaints in these areas; and

(e) what are the reasons for power failure in the area and what steps are being taken to restore the power supply fully and prevent frequent disruption in power supply?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) to (e) There have been some interruptions in power supply in Laxmi Nagar, Shakarpur (Trans Yamuna) during June-July, 1993. Some residents of the area are reported to have demonstrated at DESU offices to protest against power disruptions. Power breakdowns in this area occur mainly due to overloading of the system since a large number of commercial/industrial units have come up in the residential area. Every efforts is made by DESU to attend to the breakdown and to restore the power supply at the earliest. DESU is also taking steps within the available resources to augment and strengthen the power supply system in the area to minimise the disruptions.

Loan for NTPC power project

1010. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to a newsitem which appeared in the Hindustan Times of 16th July, 1993 captioned "Funds for matching huge foreign loan stump NTPC";

(b) if so, the details thereof indicating the amount of loan in billion dollars in respect of each power project against which matching fund in required by N.T.P.C.;

(c) whether it is a fact that in the absence of required matching fund, Government propose to throw open the doors to higher private sector for participation in India's power section;

(d) if so, which are the projects likely to be under private sector and those under the public sector separately and the total amount required by the Ministry of Power during 1993-97 in this regard indicating the manner in which such projects are proposed to be funded/implemented?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes, Sir.

(b) The World Bank has recently approved a loan of US $400 million to the National Thermal Power Corporation